आयोजना 2014-2015 की विशेषताएं
Highlights of Plan 2014-2015

सरकार ने बजट अनुमान 2014-15 (आयोजना) से, केंद्रीय प्रायाजित योजनाओं को पुन तैयार किया है। तदनुसार, 126 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को 66 स्कीमों में फिर बनाया गया है। इनमें 17 फ्लैगशिप कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं। बजट अनु. 2014-15 में, इन योजनाओं के अंतर्गत निधियां राज्य आयोजना के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में प्रदान की गयी हैं। बजट अनुमान 2013-14 में रखे गए 1,36,254 करोड़ रुपए के मुकाबले ब. अनु. 2014-15 में राज्य आयोजना 2014-15 में रखा गया 3,38,562 करोड़ रुपए का काफी अधिक आबंटन में यह बदलाव परिलक्षित हुआ है।

Government restrucctured the Centrally Sponsored Schemes (CSSs) from BE 2014-15 (Plan). Accordingly, 126 CSSs have been restructured in 66 schemes which include 17 flagship programmes. In BE 2014-15, funds have been provided under these schemes as Additional Central Assistance to State Plan. A much higher allocation of Rs.3,38,562 crore in State Plan 2014-15 against BE 2014-15 of Rs.1,36,254 crore in BE 2013-14 reflects this change.

(₹ करोड़)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आयोजना के लिए केंद्रीय सहायता

ग्रामीण विकास

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

- 34000 वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसमें प्रौढ़ सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को राजी हों को 100 दिवस की रोजगार कानूनी गारंटी प्रदान करने हेतु। ग्रामीण क्षेत्रों को कवर कर रहे सभी जिलों को 01.04.2008 से नरेगा के तहत लाया गया है।

आजीविका

- 4000 गरीब परिवारों को लाभप्रद स्व-रोजगार तथा कुशल मजदूरी रोजगार अवसरों की पहुंच से सशक्त बनाकर उनकी गरीबी दूर करने हेतु। आजीविका अ.जा./अ.ज.जा., महिलाओं, अल्पसंख्यकों तथा विकलांग लोगों सहित समाज के संवेदनशील तबकों की पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करेगी।

ग्रामीण आवास

- 16000 इन्दिरा आवास योजना के तहत गावों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को मकानों के निर्माण तथा कच्चे मकानों को पक्का करने हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए। घरों के निर्माण के लिए कुल आवंटन की 60% राशि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे अनु.जाति/अनु.ज.जाति के परिवारों के लिए है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

- 13000 अच्छी बारहमासी सड़कों के जरिए कनेक्ट न हुए पात्र ग्रामीण निवासियों हेतु कनेक्टिविटी की व्यवस्था कराने हेतु। मौजूदा ग्रामीण सड़कों का व्यवस्थित स्तरोन्नयन भी इस स्कीम का अनिवार्य भाग है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

- 10635 गरीबों को राज्यों द्वारा प्रदान किये जा रहे लाभों के अतिरिक्त सामाजिक सहायता हेतु न्यूनतम राष्ट्रीय मानदण्ड सुनिश्चित करने के लिए।

पेयजल आपूर्ति

- 11000 सभी ग्रामीण बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयासों में राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु।
- 4260 ग्रामीण स्वच्छता हेतु।

भूमि संसाधन

- 3500 एकीकृत जल संभर प्रबन्ध कार्यक्रम हेतु।

कृषि तथा सहकारिता

- 9864 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्य आयोजना) हेतु।
- 2200 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु।

(₹ in Crore)

Central Assistance to States/UT Plan

RURAL DEVELOPMENT

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

- 34000 for providing a legal guarantee of 100 days of wage employment in a financial year to every rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. All the districts covering rural areas have been brought under NREGA with effect from 01.04.2008.

Aajeevika

- 4000 for reducing poverty by enabling the poor households to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities. Aajeevika would ensure adequate coverage of vulnerable sections of the society including SCs/STs, women, minorities and persons with disabilities.

Rural Housing

- 16000 for providing assistance to rural BPL households for construction of houses and upgradation of kutcha houses under Indira Awaas Yojana. 60% of the total allocation is for construction of houses for BPL families of SCs/STs.

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana

- 13000 for providing connectivity to eligible unconnected rural habitations through good all-weather roads. The systematic upgradation of existing rural roads is also an essential component of the scheme.

National Social Assistance Programme

- 10635 for ensuring minimum national standard for social assistance to poor in addition to the benefits that States are providing.

DRINKING WATER SUPPLY

- 11000 for supplementing the States in their effort to provide safe drinking water to all rural habitations.
- 4260 for rural sanitation.

LAND RESOURCES

- 3500 for Integrated Watershed Management Programme.

AGRICULTURE AND COOPERATION

- 9864 for Rashtriya Krishi Vikas Yojana (State Plan).
- 2200 for National Food Security Mission.

- 2200 एकीकृत बागवानी विकास मिशन हेतु।
- 1898 राष्ट्रीय स्थायी कृषि मिशन हेतु।

पर्यावरण तथा वन

- 665 पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण और राष्ट्रीय नदी संरक्षण हेतु।

स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता

- 27635 सर्व शिक्षा अभियान हेतु।
- 13152 स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु।
- 4965 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु।

उच्च शिक्षा

- 2000 राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान हेतु।

महिला तथा बाल विकास

- 18691 एकीकृत बाल विकास सेवाओं हेतु।
- 725 किशोरी सशक्तीकरण हेतु राजीव गांधी योजना हेतु।
- 715 इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना और साहस सहित राष्ट्रीय महिला सशक्ततीकरण मिशन हेतु।
- 400 एकीकृत बाल संरक्षण योजना हेतु।

सूचना प्रौद्योगिकी

- 800 ई-गवर्नेंस कार्य्रक्रम हेतु।

शहरी विकास

- 7060 जेएनएनयूआरएम की योजना हेतु।

कपड़ा

- 292 राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम हेतु।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता

- 2348 अनुसूचित जाति विकास योजना।

जनजातीय कार्य

- 2517 एक मुश्त अनुदान के लिए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास

- 950 संसाधनों के गैर-व्यपगत केंद्रीय पूल हेतु।

अल्पसंख्यक मामले

- 1242 बहु-क्षेत्रक विकास कार्यक्रमों हेतु।

पंचायती राज

- 1006 राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान हेतु।

(वास्तविक लक्ष्य)

उर्वरक

- 133.68 लाख मी. टन लक्षित नाइट्रो जनित उर्वरक उत्पादन।
- 49.49 लाख मी. टन लक्षित फास्फोरसयुक्त उर्वरक उत्पादन।

कोयला और लिग्नाइट

- 638 मि.टन वर्ष 2014-15 के दौरान कोयले की घरेलू उपलब्धता आंकी गई है, जो कोल इंडिया लि. और अन्य से पूरा करने का अनुमान है।
- 25.60 मिलियन टन 2014-15 के दौरान लिग्नाइट उत्पादन का अनुमान।

इस्पात

- 29.00 मिलियन टन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा लौह अयस्क उत्पादन का लक्ष्य रखा गया।
- 17.95 मिलियन टन भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. और राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. द्वारा विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

- 4500 मेगावाट पवन, लघु पनबिजली, बायोमास विद्युत/सह उत्पादन, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा और सौर शक्ति से ग्रिड-इंटरएक्टिव विद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए।
- 1.20 लाख पारिवारिक किस्म के बायोगैस संयंत्रों का विनिर्माण।

- 2200 for Mission for Integrated Development of Horticulture.
- 1898 for National Mission for Sustainable Agriculture.

ENVIRONMENT AND FORESTS

- 665 for Ecology and Environment and National River Conservation.

SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

- 27635 for Sarva Shiksha Abhiyan
- 13152 for National Programme of Mid Day Meals in Schools.
- 4965 for Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan.

HIGHER EDUCATION

- 2200 for Rashtriya Uchha Shiksha Abhiyan.

WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

- 18691 for Integrated Child Development Services.
- 725 for Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls.
- 715 for National Mission for Empowerment of Women including Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana and SAAHAS.
- 400 for Integrated Child Protection Scheme.

INFORMATION TECHNOLOGY

- 800 for National e-Governance Action Plan.

URBAN DEVELOPMENT

- 7060 for the scheme of JnNURM.

TEXTILES

- 292 for National Handloom Development Programme.

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

- 2348 for scheme for development of Scheduled Castes.

TRIBAL AFFAIRS

- 2517 for Block Grants.

DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

- 950 for Non Lapsable Central Pool of Resources.

MINORITY AFFAIRS

- 1242 for Multi-Sectoral Development Programmes.

PANCHAYATI RAJ

- 1006 for Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan.

(Physical Targets)

FERTILISERS

- 133.68 lakh MT of Nitrogenous Fertiliser production targeted.
- 49.49 lakh MT of Phosphatic Fertiliser production targeted.

COAL AND LIGNITE

- 638 million tones of domestic production of Coal has been estimated during 2014-15, which is projected to be met from Coal India Limited and others.
- 25.60 million tones of Lignite production estimated during 2014-15.

STEEL

- 29.00 million tonnes of Iron ore production targeted by National Mineral Development Corporation Ltd.
- 17.95 million tones of saleable steel production by Steel Authority of India Ltd. and Rashtriya Ispat Nigam Ltd. targeted.

NEW AND RENEWABLE ENERGY

- 4500 MW Grid-interactive Power capacity addition from wind, small hydro, biomass power/cogeneration, urban and industrial waste to energy and solar power.
- 1.20 lakh - construction of family type Biogas plants.